

प्रभु,

एन०ए०ए०न०प०ल०ध्या०,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादून दिनांक: २० दिसम्बर, २००७

विषय:- उत्तराखण्ड में चार घाम यात्रा तथा अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव के लिये जनपद देहरादून में बार्डर रोड आर्गनाइजेशन के चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट कार्यालय की स्थापना हेतु १८.३० एकड़ भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-१५०७/१२ए-११४(२००५-०८) दिनांक १० अक्टूबर, २००७ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड में चार घाम यात्रा तथा अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव के लोक प्रयोजन के लिये जनपद देहरादून में बार्डर रोड आर्गनाइजेशन के चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट कार्यालय की स्थापना हेतु घाम गांजरी ग्रान्ट तहसील ऋषिकेश जनपद देहरादून में सीलिंग से प्राप्त १८.३० एकड़ भूमि को शासनादेश संख्या-५५८/१६(१)/७३-रा-१ दिनांक ९ मई, १९८१ तथा शासनादेश संख्या-१६९५/९७-१-१ (६०) ९३-रा-१ दिनांक १२-९-९७ में दिये गये प्राविधानों एवं ३०९० अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम १९६० (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा २५ के अनुरूप वर्तमान बाजार मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा करने एवं वर्तमान दर पर निकासी गयी गालगुजारी के सौ गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- (१) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।
- (२) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से ०३ (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (३) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-१५०/१/ ६५(२४)-रा०-६ दिनांक ९ अक्टूबर, १९८७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट १९९५ के अधीन पट्टा प्रथमतः ३० वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार ३०-३० वर्षों के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो भूतल लगेन के १-१/२ गुना से कम नहीं होगा।

- (4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता घटतेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।
- (5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा आर्गनाइजेशन का विघटन हो जाता है, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भागों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- (6) आर्गनन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु सं० 1 से 5 तक की किसी भी शर्त का उत्पन्न होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि में निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2- उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन०एस०नमलखाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- महानिदेशक, सीमा सड़क महानिदेशालय, सीमा सड़क भवन रिंग रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली-110010
- 4- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 5- मार्ट फाईल।

आज्ञा, से.
(सन्तोष बरौनी)
अनुसचिव।